‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.11.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज ;राम राजद्ध चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 24 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 नवंबर, 2016

आजतक और अन्य चैनलों पर प्रसारित डॉ. उदित राज का बयान

खेलों में मिले आरक्षण

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2016.

परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों को खेल के क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि खेल के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाना है तो खेल के क्षेत्र में भी दलितों की भागेदारी होनी चाहिए। ऐसे कई देश हैं, जहाँ पर वंचितों को खेल में आरक्षण दिया जाता है यदि साउथ अफ्रीका कि बात करें तो वहां का मुख्य खेल क्रिकेट है और वहां पर अश्वेतों को आरक्षण दिया गया है जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। वर्तमान समय में साउथ अफ्रीका में यह कानून है कि वहां की क्रिकेट की टीम में 5 से अधिक श्वेत खिलाडी नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में भी कहीं न कहीं क्रिकेट को सर्वमान्य जगह दी जाती है जबकि भारत में खेल के स्तर को देखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। यदि वर्तमान समय में ओलम्पिक, हाकी जैसे खेलों में आरक्षण होता तो निश्चित ही हमारा देश और भी आगे होता। अब समय आ गया है कि

दलितों की भागीदारी को बढाया जाए जिसके लिए मैं 28 नवम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महा रैली का आयोजन कर रहा हूँ जिसके लिए पूरे देश के दलितों का आह्वाहन कर रहा हूं। यदि पूरे देश के दलित एक जुट हो जाएं तो सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और उन्हें उनकी भागेदारी के लिए सरकार को कदम बढ़ाना ही होगा। ✦✦✦

28 नवंबर की रैली के लिए आर्थिक सहयोग एवं अन्य निर्देश

साथियों,

क्या एक या दो दिन काम रोकने या छुट्टी ले लेने से आर्थिक हानि या आराम में फर्क पड़ जाएगा ? जबकि पूरे साल काम और धंधा करते रहते हैं। इससे न तो लोग गरीब होगें न ही आराम और पारिवारिक सुख में कमी होगी, लेकिन एक दिन सभी रामलीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्रित हो जाएं तो ताक़तवर बनने शुरु हो जाएंगें और आने वाले दिनों में परिवार भी खुशहाल हो सकेगा। आप सभी को पता ही है कि वर्तमान में कालेधन को रोकने के अभियान के कारण 500 एवं 1000 मूल्य के पुराने नोट अमान्य हो चुके हैं। यद्यपि इस मुहिम से काले धन की रोकथाम में बड़ी सहायता मिलेगी लेकिन 28 नवंबर, 2016 को रामलीला मैदान, दिल्ली में आयोजित 19वीं महा रैली को सफल बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े लोगों को अपने से नीचे के लोगों के विकास हेतु सहयोग करना चाहिए। आप लोगों में से जो इसे अपनाएं वे परिसंघ के आंदोलन का हिस्सा बने और नकद, चेक, ड्राफ्ट या सीधे बैंक खाते में सहयोग राशि प्राप्त होती ही रही है। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे आंदोलन से बहुत से अधिकार सुरिक्षत कराए गए।

परिसंघ के साथियों से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक ऑनलाइन डोनेशन परिसंघ के खाते में जमा कराएं। ऑनलाइन ट्रांजेक्सन की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित के पास नकद और परिसंघ के बैंक खाते में पुराने 500 और 1000 के नोटों से चंदा जमा कराया जा सकता है। खाते का विवरण नीचे छापा जा रहा है –

Customer Name: ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANISATION
Account no: 30899921752, CIF No: 85626065749
Saving Bank Account State Bank of India Chandralok Building
IFSC Code: SBIN0001639

रैली हेतु संपर्क सूत्र

जिन्हें प्रचार सामाग्री नहीं मिली है, वे राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित कुमार से सम्पर्क करके मंगवा लें और अपनी ओर से भी स्थानीय साथियों के नाम के साथ छपवाकर वितरित करें। जिन साथियों के मोबाइल नंबर, ईमेल, व्हाट्सअप, फेसबुक हमारे पास है, उन्हें सूचनाएं भेजी जाती रहती हैं। जिन्हें सूचनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं उनके भी विवरण भेजें, जिससे कि राष्ट्रीय कार्यालय से रैली के संबंध में सूचनाएं भेजी जा सकें। रैली में भाग लेने के लिए जो साथी रेलवे में सीटें आरक्षित करवा चुकें हैं और वेटिंग में है, विवरण ईमेल या व्हाट्सअप या एसएमएस द्वारा भेजें, जिससे कि सीटें कन्फर्म करायी जा सकें। जिन्होंने नहीं कराया है, अतिशीघ्र करवा लें। रैली में भाग लेने हेतु दिल्ली में ठहरने एवं खाने की व्यवस्था की जानकारी हेतु संजय राज मो. 9654142705, रेलवे कर्मचारी–अधिकारी सूचनाएं प्राप्त करने व अन्य जानकारी हेतु राष्ट्रीय कार्यालय में सचिन मो. 9560035350, परिसंघ से संबंधित जानकारी एवं प्रचार सामाग्री प्राप्त करने, रेलवे के पी.एन.आर. भेजने एवं अन्य जानकारी हेतु सुमित मो. 9868978306, से सम्पर्क करें। कितने साथियों के साथ रैली में भाग लेगें, यदि इसकी सूचना अग्रिम में दे दी जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे कि ठहरने एवं खाने–पीने की व्यवस्था पहले से ही की जा सके।

AIParisangh
9899766443
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

– डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

खटीक समाज चला अम्बेडकर की ओर

खटीक समाज चला अम्बेडकर की ओर

खटीक समाज जागरूकता संघर्ष संघ 8 नवंबर, 2016 को मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में 12 प्रांत के प्रदेशों के खटीक समाज के गौरवशाली प्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने सभा को संबोधित किया और इन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी दबे-कुचलों व गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा। 1997 में तीन आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे जिसमें से तीन हमारे आंदोलन की बदौलत वापिस हुए। अगर ऐसा न किया होता तो इस देश के दलित समुदाय की हालत और भी बुरी होती। तो इस समुदाय को भी अपनी लड़ाई को खुद लड़ने की तरह समझकर बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे आपका अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके। हम सम्पूर्ण दलित समाज के अधिकारों को सुरक्षित कराने के लिए तत्परता से कदम आंदोलन के मैदान में डटाए रखे हैं। इस दलित-खटीक समुदाय के बारे में भी लोक सभा में जिन-जिन प्रदेशों में अनुसूचित जाति में खटीक जाति शामिल नहीं की गयी है, उसे अतिशीघ्र शामिल कर संवैधानिक अधिकार मुहैया कराए जाएं।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संजय राज खटीक एवं राष्ट्रीय महासचिव - इन्द्रेश चन्द्र खटीक पूरे देश के सम्पूर्ण खटीक समाज के संगठनों को एक जुटकर उनके अधिकार एवं भागीदारी सुनिश्चित करेगा। चाहे वह पूरे देश में अनुसूचित जाति की बात हो या देश में समान शिक्षा की बात हो या भूमिहीनों को भूमि दिलाने की बात हो। इन सभी गंभीर मुद्दों को एक प्रतिज्ञा के तौर पर तत्परता से संघर्ष कर अपने पाले में सुनिश्चित करेगा। चाहे हमें देशव्यापी आंदोलन करना पड़े या केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों से टकराना पड़े। हम वे सभी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करके रहेंगे। अतिशीघ्र यह संगठन देश व्यापी बड़ा आंदोलन का रुख लेने जा रहा है।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज को आश्वसन दिलाया गया कि आगामी 28 नवंबर, 2016 को रामलीला मैदान, दिल्ली में दलित अधिकारों के लिए आयोजित महारैली में खटीक समाज बढ़-चढ़कर भागीदारी लेगा।

- इन्द्रेश चन्द्र खटीक
9650206337

+++

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

All India Confederation of SC/ST Organisations

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

19वीं महा रैली

28 नवंबर, 2016
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

डॉ. उदित राज
पूर्व आई.आर.एस.
राष्ट्रीय अध्यक्ष

साथियो,

हम दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की समस्या केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। सरकार किसी की हो समस्याएं कम और ज्यादा के रूप में रहेगीं ही। जहां दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी अत्याचार होते थे। 1997 में जब सामाजिक न्याय की सरकार केन्द्र में थी तो पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। बाबा साहब ने कहा था कि राजनैतिक जनतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक जनतंत्र कायम होगा और इसके लिए सामाजिक परिवर्तन - जैसे बौद्ध धम्म की दीक्षा, पाखंड का त्याग, जातिविहीन समाज, कम से कम दलितों में जात-पांत का खात्मा आदि। इससे यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हर हाल में हजारों वर्षों की असमानता और शोषण से हम सभी को स्वयं तो लगातार लड़ना ही होगा, सरकार चाहे जिसकी हो। मां-बाप ने जन्म दिया लेकिन आरक्षण बाबा साहब के प्रयास से मिला। आरक्षण केवल अपने उपभोग के लिए ही नहीं है, बल्कि संघर्ष करने के लिए। इसलिए चाहे मंत्री हों या सांसद या प्रधान या अधिकारी-कर्मचारी सभी समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिनिधि हैं। झज्जर (हरियाणा) में गाय की खाल की खातिर 5 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया और हाल में उना (गुजरात) में क्या हुआ, हम सभी जानते हैं। अभी भी हमें कुछ लोग जानवरों से बदतर समझते हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदशों की वापिसी के लिए हुआ और उसके बाद धरना-प्रदर्शन व आंदोलन शुरू हुआ। 11 दिसंबर, 2000 को रामलीला मैदान, दिल्ली की रैली आज़ाद भारत की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी और सरकार पर दबाव बना जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए और छिने अधिकार वापिस मिले। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संघर्ष की शुरुआत हमने ही की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से मशहूर मुकदमा जो 85वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित था, की पैरवी हमने ही की और जीते। पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के खिलाफ सवर्णों के आंदोलन का भरपूर विरोध किया और इस अधिकार को लेकर रहे। अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण जो लोकपाल बिल बन रहा था हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश करके उसमें आरक्षण कराया। वरना दलितों व पिछड़ों को जातीय आधार पर फर्जी मामले में फंसाने का यह सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनता। 2008 में तत्कालीन उ0प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा आदेश जारी किया गया कि अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत 22 अपराधों में से सिर्फ बलात्कार एवं हत्या के मामले ही दर्ज किए जाएंगें, शेष मामलों में यह एक्ट नहीं लगेगा। तब हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके इसे दुरुस्त कराया। इस अधिनियम में दिसंबर 2015 में संसद में संशोधन हुआ और अब 123 प्रकार के अपराध इसमें शामिल हैं।

पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद से पास होना है। आशा थी कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे कराने के लिए महासंघर्ष करना पड़ेगा। जब से डॉ. उदित राज सांसद बने हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ा, सवाल उठाने का और शायद ही कोई और सांसद इतना किया होगा (इसे बेबसाइट www.uditraj.com/gallery/video vkSj www.youtube.com/user/druditraj पर देखा जा सकता है)। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में डॉ0 उदित राज ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रतिस्थापित किया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या सवर्णों को चाहिए ? डॉ. उदित राज ने अपना काम कर दिया है, समाज क्यों सो रहा है ? क्यों नहीं लाखों-करोड़ों सड़क पर उतरते और सभी दलों पर दबाव डलवाकर संवैधानिक संशोधन कराकर निजी क्षेत्र में आरक्षण का अधिकार लें। आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी और एडहाक नियुक्ति के जरिए आरक्षण लगभग आधा खत्म किया जा चुका है। इसके खिलाफ तो संघर्ष करना ही है लेकिन बिना निजी क्षेत्र में आरक्षण लिए गुजारा नहीं होगा। खाली पदों पर भर्ती, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, एक राज्य के जाति प्रमाण-पत्र की सभी राज्यों में मान्यता, समान शिक्षा, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि मांगों को लेकर 28 नवंबर, 2016 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे भारी संख्या में विशाल रैली में शामिल होकर ऐसा कर दिखाएं कि यह अधिकार मिलकर रहे।

निवेदक

ब्रह्म प्रकाश, परमेन्द्र, विनोद कुमार, रवीन्द्र सिंह, एन.डी. राम, रामनंदन राम (दिल्ली), जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, केदारनाथ, सुशील कुमार, नीरज चक, निर्देश कुमारी (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, सिद्धार्थ कांबले, सूर्यकांत किवांडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, डॉ. मुख्तियार सिंह, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह, दर्शन सिंह चंदेढ़, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, रंजीत मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद आर्या (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र कुमार (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, नवल सोलंकी (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल (तमिलनाडु), के. कृष्णन कुट्टी, बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर, जे. बी. राजू (तेलंगाना), डॉ. श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छ.ग.), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, विश्वजीत साह (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, एल.एम. ओरांव (झारखंड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेन्द्र, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, चन्नप्पा (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम).

AIParisangh
9899766443
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

रैली की सफलता हेतु आरक्षण बचाओ रथ यात्रा

अनुसूचित जाति /जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने आरक्षण बचाओ यात्रा का शुभारम्भ किया है। आरक्षण बचाओ यात्रा डॉ. उदित राज के नेतृत्व में दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख स्थानों नई दिल्ली, करोल बाग, चांदनी चौक, केशवपुरम, नजफगढ़, दक्षिणी दिल्ली, मयूर विहार और शाहदरा से होते हुए निकाली जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, दिल्ली सरकार द्वारा लाखों कर्मचारियों को पक्का कराने, दलित उत्पीडन के खिलाफ एवं दलितों के सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागरुक करना और 28 नवंबर, 2016 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित महा रैली में भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित करना है।

डॉ. उदित राज का कहना है कि लगातार आरक्षण को समाप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। जब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यदि दलितों और वंचितों से उनका एक मात्र आरक्षण का अधिकार भी छीन लिया जायेगा तो उनका विकास कैसे हो पायेगा और वह समय होने लगी। आज समय आ गया है कि बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए हमे अपने संघर्ष को आन्दोलन के रूप में लड़ना होगा। दलितों के लिए सिर्फ एक ही चुनौती नहीं है कि सिर्फ आरक्षण बचाना है बल्कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाये उसके

के साथ और पिछड़ते चले जायेंगे। दलितों को पिछड़ेपन और गुलामी में जकड़े हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं। आज हम आजाद भारत के नागरिक जरुर कहलाते हैं लेकिन जब दलितों की स्थिति की बात आती है तो जस कि तस बनी हुई है। यदि दलितों को अपनी स्थिति बेहतर करनी है तो आरक्षण को बचाने के लिए उन्हें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। आज बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन उसके बाद फिर दलितों की स्थिति बदतर लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अगर आज निजी क्षेत्र में आरक्षण होता तो सभी क्षेत्रों में इनकी भागेदारी होती। जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, जैसे व्यवसाय, कला एवं संस्कृति, फिल्म-मीडिया, आयात-निर्यात आदि में इनकी भागेदारी नगण्य है। लेकिन यह सब अभी भी किसी सपने से कम नहीं है। यदि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को गन्दगी से निकल कर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो उन्हें इस महा रैली में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। दलितों को अपने वजूद को दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा।

✦✦✦

28 नवंबर, 2016 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में अजा/जजा परिसंघ की रैली में आने-जाने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त कोच की व्यवस्था रेलवे ने की है। परिसंघ के नेता संबंधित अधिकारियों से मिलकर अतिरिक्त कोच लगवाने की व्यवस्था कर लें

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

FAX/POST COPY
ISSUED ON 02.11.2016

THE GENERAL MANAGERS (OPTG.)	COPY TO:-
CR/MUMBAI	CPTM/CR/MUMBAI
ECR/HAJIPUR	CPTM/HAJIPUR
ECOR/BHUBANESWAR	CPTM-BHUBNESHWAR
ER/KOLKATA	CPTM/ER/KOLKATA
NR/NEW DELHI	CPTM/NEW DELHI
NER/GORAKHPUR	CPTM/NER/GORAKHPUR
NWR/JAIPUR	CPTM-NWR/JAIPUR
NCR/ALLAHABAD	CPTM/NCR/ALLAHABAD
NFR/GUWAHATI	CPTM/NFR/GUWAHATI
SR/CHENNAI	CPTM/SR/CHENNAI
SWR/HUBLI	CPTM/SWR/HUBLI
SECR/BILASPUR	CPTM/SECR/BILASPUR
SCR/SECUNDERABAD	CPTM/SCR/SOUTH CENTRAL RAILWAY
SER/KOLKATA	CPTM/SER/KOLKATA
WR/MUMBAI	CPTM/WR/MUMBAI
WCR/JABALPUR	CPTM/WCR/JABALPUR

NO.91/CHG.II/G3/NF/5 PT-II () DR. UDIT RAJ, MP, NATIONAL CHAIRMAN, ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANISATIONS HAS REQUESTED FOR ATTACHING EXTRA COACHES FOR ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANISATIONS DELEGATES ATTENDING THEIR CONVENTION AT NEW DELHI ON 28.11.2016 () MINISTRY OF RAILWAYS DESIRES THAT RAILWAYS MAY CONSIDER THE REQUEST OF SHRI UDIT RAJ ON FULL TARIFF RATES SUBJECT TO OPERATIONAL FEASIBILITY AND AVAILABILITY OF REQUIRED COACHING STOCK () IT SHOULD BE ENSURED THAT ALL THE NECESSARY COMMERCIAL FORMALITIES INCLUDING REALISATION OF DETENTION, HAULAGE CHARGES AS PER EXTANT RULES, ARE COMPLETED BEFORE STARTING THE JOURNEY BY THE PARTY () TAKE ACTION ACCORDINGLY AND CONFIRM () GUHA RAILWAYS ()

(Niraj Verma)
Director Tfc. Trans (Chg.)-I
Railway Board

COPY TO:

1. EDPM, ED(C&IS), RAILWAY BOARD FOR INFORMATION AND NECESSARY ACTION.
2. SHRI UDIT RAJ, MP, T-22, ATURL GROVE ROAD, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001.

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

क्यों नहीं मुस्लिम या ईसाई की संख्या कम होती है और हिन्दू की ही होती है। क्यों धर्मांतरण हिन्दू ही करते हैं। लेखक ने बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी पर चिंता की है। बेहतर होता कि हिन्दू धर्म के अंदर की खामियों को रेखांकित करते जो बार-बार कहते थकते नहीं कि हमारी महान परंपराएं हैं और हम विश्वगुरू हैं, क्या वे यह भी कहते हैं कि स्कूल में दलित बच्चों के साथ सवर्ण बच्चे खाते नहीं। दलित के हाथ से बने खाने को नन्हें-मुन्ने सवर्ण के बच्चे खाते नहीं हैं। कितना ज़हर समाज में घुला है और इसी वजह से कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली, श्रीलंका, ईरान, ईराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आदि जगहों से हिन्दू धर्म खत्म हुआ। काश ! हिन्दू समाज में जात-पांत न होता तो मज़ाल कि भारत के बाहर रह रहे हिन्दू चाहे बांग्लादेश या पाकिस्तान में होते, उनको कोई असुरक्षित कर सकता? बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर एक और श्रेष्ठ भारत का निर्माण जातिविहीन समाज की स्थापना से करना चाहते थे। इजराइल छोटा सा देश है, बीसों दुश्मन देशों से घिरा है लेकिन काई उसका बाल-बांका नहीं कर सकता क्योंकि उनका समाज एक है।

– डॉ. उदित राज

पाकिस्तान बनता बांग्लादेश

बांग्लादेश में हाल में दस दिनों के भीतर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से दो हमले हुए वह वहां लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमले दरअसल उस देश के लोकतंत्र पर ही सवाल है। पहले बांग्लादेश के ब्रातण बेड़िया जिले में हिंदुओं के कम से कम दस मंदिरों और सैकड़ों घरों को ध्वस्त कर दिया गया और उसके हफ्ताभर बीतते-बीतते उपजिला के मध्यमपाड़ा और दक्षिणपाड़ा में हिंदुओं के कई घरों में आग लगा दी गई। इसी वर्ष जून महीने में बांग्लादेश में चार हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जिसमें से दो लोग मंदिरों के रखरखाव से जुड़े थे। इस समय बांग्लादेश में कहीं हिंदू तो कहीं बौद्ध भिक्षु निशाना बन रहे हैं तो कहीं ईसाई समुदाय के लोग। बांग्लादेश में इस समय के हालात 1992 के हालात की याद को ताजा कर रहे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस को आधार बनाते हुए 1992 में बांग्लादेश में हिंदुओं के 28 हजार रिहायशी मकानों, 22 सौ वाणिज्यिक उद्यमों और 36 सौ मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था। तब बारह हिंदू मारे गए, दो हजार घायल किए गए और दो हजार महिलाओं व युवतियों के साथ ज्यादती हुई थी। 1 बांग्लादेश के हिंदू व बौद्धों की सबसे अधिक आबादी दौचंगा, मेहरपुर, जेसोर और डोनाइडाह जिलों में है और उन पर हमले भी वहीं होते रहे हैं। हमलों से बचने के लिए ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक वहां से पलायन करते रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही हिंदुओं का विस्थापन आरंभ हुआ। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1974 से 1991 के बीच रोज औसतन 475 लोग यानी हर साल एक लाख 73 हजार 375 हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य हुए। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी सवा तीन करोड़ होती। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में हिंदुओं की आबादी 28 प्रतिशत थी, जो 1951 में 22 प्रतिशत, 1961 में 18.5 प्रतिशत, 1974 में 13.5 प्रतिशत, 1981 में 12.13 प्रतिशत, 1991 में 11.6 प्रतिशत और आज घटकर 8.2 प्रतिशत हो गई है। बांग्लादेश की करीब 16 करोड़ आबादी में से अल्पसंख्यकों की तादाद सवा करोड़ है, जो फिलहाल खौफ में जीने को विवश हैं। हमलों से बचने के लिए बांग्लादेशी हिंदू भागकर बंगाल, त्रिपुरा और असम में आश्रय लेते रहे हैं। विडंबना यह है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और भारत आने पर उन्हें रिफ्यूजी या घुसपैठिया कहा जाता है। बांग्लादेश के जो हिंदू भारत आ गए वे कभी नहीं लौटे। बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी भी बंगाल और अन्यत्र आकर सम्मानपूर्वक रह लेते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फेरी लगाते हैं, रिक्शा खींचते हैं और तरह-तरह के काम कर पैसा कमाकर जीवन काटते हैं, किंतु उस पार लौटने की सपने में भी नहीं सोचते। 1 बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के पलायन के मूलतरू पांच कारण हैं। ये हैं-सांप्रदायिक उत्पीड़न, सांप्रदायिक हमले, शत्रु अर्पित संपत्ति कानून, देवोत्तर संपत्ति पर कब्जा और सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की उपेक्षा एवं भेदभाव। बांग्लादेश में शत्रु अर्पित संपत्ति कानून और देवोत्तर संपत्ति पर कब्जे ने अल्पसंख्यकों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इसके अलावा उस पार हिंदुओं को भारत का समर्थक अथवा

(शेष पेज 5 पर....)

आगामी रैली से संबंधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

(पेज 4 का शेष ....)

एजेंट अथवा काफिर कहकर गाली दी जाती है। इसे बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के इस्लामी जिहाद के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह वहां के इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं और बौद्धों पर आक्रमण कर रहे हैं उसका एकमात्र मकसद देश को अल्पसंख्यकों से पूरी तरह खाली करा लेना है। सवाल है कि कट्टरपंथी क्या बांग्लादेश को एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए पाकिस्तान के कई शुभ बुद्धि संपन्न बुद्धिजीवी तक मानते हैं कि बांग्लादेश लोकतंत्र के मामले में पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान इस मामले में

नाकामी का खतरा 16

शेख हसीना यदि बांग्लादेश को कट्टरता के दौर से बाहर नहीं निकाल पातीं तो उनके शासनकाल की यह एक बड़ी विफलता मानी जाएगी।

बड़ा अभागा देश है कि वहां एक समूची पीढ़ी सैनिक शासन में पली और बड़ी हुई। लोकतंत्र के कमजोर होने के कारण ही पाकिस्तान में तालिबानी ताकतें फल-फूल रही हैं। वहां लोकतंत्र लगभग बंदूक की नोक पर चल रहा है। बांग्लादेश को आज यदि पाकिस्तान से बेहतर माना जा रहा है तो इसलिए कि किसी भी देश की प्रतिष्ठा इसी से बनती है कि अल्पसंख्यकों के प्रति वहां कैसा व्यवहार होता है। आज सबसे बड़ी चिंता दुनिया में हर जगह बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक का सांप्रदायिक उत्पीड़न है। बांग्लादेश के संदर्भ में भी यही सही है। इसलिए मजूबत लोकतांत्रिक देश के रूप में बनना या बिगड़ना, दोनों चीजें बांग्लादेश के हाथ में हैं। यदि बनना है और पाकिस्तान से बेहतर छवि बनाए रखनी है तो अल्पसंख्यकों पर जुल्म रोकने के लिए उसे कठोर कदम उठाने होंगे। अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रहने से बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। इसलिए बांग्लादेश यदि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रोकता तो वह अपनी गरिमा और आभा खो देगा। बांग्लादेश में यदि अल्पसंख्यकों के भीतर बैठा भय दूर नहीं किया जाता तो वह उस देश में लोकतंत्र के कमजोर पड़ने का प्रमाण होगा और जब तक वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो अग्रगामी व प्रगतिशील ताकतें भी मजबूत नहीं होंगी। इसलिए अल्पसंख्यकों पर हमले करने वालों को कुचलने के लिए बांग्लादेश सरकार को तेजी से सक्रिय होना होगा। वहां धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार अब और अधिक खामोश न रहें। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करने का ठोस रास्ता निकालना होगा। शेख हसीना यदि बांग्लादेश को कट्टरता के दौर से बाहर नहीं निकाल पातीं तो उनके शासनकाल की यह एक बड़ी विफलता मानी जाएगी।

(लेखक : कृपाशंकर चौबे, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र के प्रभारी हैं)

✦ ✦ ✦

चलो दिल्ली ! चलो दिल्ली !! चलो दिल्ली !!!

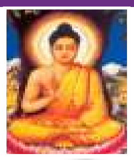
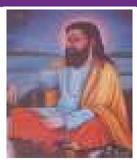
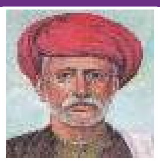

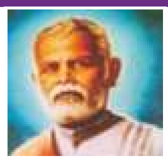
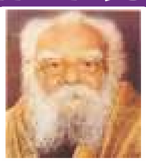

EDUCATE AGITATE ORGANISE

NSOSYF

NATIONAL SC,ST,OBC STUDENT & YOUTH FRONT

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसंघ
एवं मुख्य मार्गदर्शक नसोसवाईएफ

महारैली

28 नवंबर, 2016,(सोमवार) प्रातः 11 बजे
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

मुख्य मांगे : ◆ निजी क्षेत्र, पदोन्नति, सेना और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण दो। ◆ इंटर तक 3000 रूपये, एम.ए. तक 5000 रूपये प्रतिमाह एवं शोध करने वाले सभी छात्रों को राजीव गांधी एवं मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप मिले, ◆ बुध्द, फुले, साहू, पेरियार एवं बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जी को गांधी जी एवं नेहरू की तरह पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ◆ सभी छात्र-छत्राओं को छात्रावास मुहैया कराया जाए ◆ सभी राज्यों में लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू की जाए।

इन माँगो को लेकर हम पहुँच रहे है, दिल्ली के रामलीला मैदान पर आप सभी भारी संख्या में आकर इस आन्दोलन का हिस्सा बने।

प्रताप सिंह अहिरवार राष्ट्रीय समन्वयक, मो. 9630511720, **अजय पासवान** राष्ट्रीय सचिव, मो. 9470410542

निवेदक :- महाराष्ट्र :- बालाजी कोंडामंगल, अजित कांबले, रवि सुर्यवंशी, स्वप्निल मुले, सतिश वागरे, स्वप्निल कांबले, **मध्य प्रदेश :-** सतेन्द्र सेगर, ए. सेन्डी सिंह, प्रकाश अहिरवार, हेमंत उपाध्याय, सचिन पटेल, प्रशांत चंदलेकर, **राज्यस्थान :-** भमर भादू, अशोक कुमार सिरणा, लक्ष्मण मीणा, लोकेश मेघवाल, **बिहार:-** विकास पासवान, आनन्दवर्धन पासवान, डॉ. ओम प्रकाश, रवि महेन्द्र, **पंजाब :-** नरेन्द्र सिंह, **उत्तराखंड :-** नितिन लामयान, **गुजरात :-** प्रकाश वनकर, **उत्तरप्रदेश :-** अलोक कुमार, नेरश कुमार, राजेश कुमार, हरिओम, अंकित चक, **दिल्ली :-** बुध्दरत्न, **छत्तीसगड :-** सुर्या रात्रे, **आध्रा प्रदेश :-** चेराबंडु राजा

मध्य प्रदेश :- मुकेश योगी, मनीष बरवे, अनिरूध्द मोरे, प्रदिप खटकर, बंटी अहिरवार, धर्मेन्द्र सिंह सूर्यवंशी, वृजेश आर्य, देवराज चौहान, विक्रम अनगोरे, पवन टान्डेकर, राजमल करोले, हेमंत सोलंकी, राजेन्द्र नरगांवे, सागर गवले, अनिल बडोले, मयुर चौहान, लोकेश गोरे, निलेश दत सुर्यवंशी, भुपेन्द्र अहिरवार, मुन्ना लाल, निखिल,विजय, यस. चौधरी, कमलाकांत, भागचन्द्र अहिरवार, रविन्द्र अहिरवार, लक्ष्मण अहिरवार, राजेश सिंह सुर्यवंशी, राहुल वर्मा, अतुल अहिरवार, माया राम, राज कुमार सरगम, राम अवतार, राजेश अहिरवार, राजेश निगम, रोहित कदम, अरविंद बोहरे, जेकी, रती राम अहिरवार, अभिजीत, कवि भिन्डे, रोशन मेहरा, राजेश ध्रुवे, प्रदीप, रश्मि अहिरवार, बृजेश, मोनिका, बबली अहिरवार, सुरेश अहिरवार, लोकेश कुमार, राहुल पांडे, **महाराष्ट्र :-** प्रविण रायबोले, संघरत्न निवंडगे, गणेश येरेकर, संदिप इंगले, प्रकाश दिपके, धम्मापाल वाढवे, मंगेश गाडगे, प्रसेंनजित गायकवाड, किरन खंदारे, किरन आंदेगांवकर, अजय जाधव, वैभव येरेकर, संचिन मुले, भीमा जोगदंड, विवेक शेवाले, राजरत्न पंडित, किरन पोले, काजल कांबले, कोमल कांबले, सचिन कांबले, सतिश महामुने, विश्वजित कांबले, राहुल वाठोरे, प्रविन सावले, रोशन अंबोरे, किशोर कांनिदे, मंगेश वानखेडे, कुमार गौरव, सुरज गवली, अविनाश कांबले, सतिश आठवले, गौतम गायकवाड, अमोल भालेराव, आकश हिवराले, माया फुलमाली, **राजस्थान:-** राहुल बिलोटीया, इन्द्रराज, पवन कुमार,अनिल पठोदिया,रमेश चौहान, अशोक, छगनलाल, झलक रेगर, नैनाराम पावा, पिन्टु कुमार, हेमराज, प्रकाश, नेमीचंद, भानाराम, सद्दाम हुसैन, कमलेश बोस, सुरेश राणा, महेन्द्र गुंडाप्रताप, लोकेश कुमार, लेख राज, जय प्रकाश, प्रहलाद सागर, राजु देओल, राहुल, तेलेश कुमार, प्रवीण जेलिया, **बिहार :-** राहुल रजक, अमरज्योति पसवान, सुरेन्द्र आजाद, सुरेन्द्र चौधरी, **हरीयाणा:-** कशमिर राण्गा, पवन कागरा, मनु खन्ना,किरन पाल, रवि महेन्द्र, **पंजाब:-** सुरिन्दर पाल छब्बु, दिलीप कुमार, हरजिन्द्र सिंह, अमित कुमार(अप्पु), **उत्ताराखंड:-** राहुल रॉय, बिपिन कुमार, रितिष लामयान, गोपाल पांवार, नितिन राय, अजय कुमार, राहुल कुमार, **पश्चिम बंगाल :-** कोयल बिश्वास, **कर्नाटक :-** शिव कांबले, शाम भावीकटे, सुनील गुलबर्गे, धर्म प्रकाश, गौतम खेरडे, **गुजरात :-** प्रशांत मोरी, अनंद परमार, हितेश सुतारिया, **आसाम :-** डॉ.आमलद, **उत्तर प्रदेश :-** श्रवण कुमार राज, अभिषेक चक, शैलेन्द्र, सुमित कुमार, राघवेन्द्र पाल, रामवीर, राहुल, रवि सिंह रब्बा, राजेश कुमार, अमित कुमार, प्रभाकर, प्रमोद कुमार, लोकेश कुमार, कुलदीप राजपुत, जोनी लहरी, विमल कुमार, सुभाष चन्द्र, मुलायम सिंह, रविकांत, चंद्रशेखर, **आध्रा प्रदेश :-** अनिल कुमार, नागेश्वर राव,नित्य कुमार, **दिल्ली :-** बृजपाल, रणवीर, हीरालाल, प्रवीण, साजिद अहमद, मीनाबोध्द, ज्योति, कोमल, विमलेश, रोहित, गौतम, वंदना, कुलदिप, रवि, अमित, रामनारायण, आदित्य, सपना, कर्तार सिंह, फूल सिंह, अभिषेक, **छत्तीसगड :-** सुमित सतनामी, खानचन्द्र कोसरीया, दीपक कोसरीया, कल्याण हरवंश, बलराम तारक, विजय रात्रे

मा. डी. हर्षवर्धन
राष्ट्रीय अध्यक्ष नसोसवाईएफ

पत्राचार :- रूम नं 7 विठ्ठल भाई पटेल हाउस, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110001

www.facebook.com/ harshvardhan dawane
www.facebook.com/Pratap Singh Ahriwar

h.dawane2013@gmail.com,
pratapsinghahriwar6@gmail.com

7709975562, 9630511720, 9470410542,
7588526831, 9921762669, 8380876777

Look Who's Talking

The most vociferous critics of reforms in Hindu law are now arguing for the UCC

Faizan Mustafa

"The best way to reform Mohammedan law is not to reform it at all. Let its inconvenient and archaic features wither away. Once it is accepted that this is the policy, it will wither away fast enough. If there is a frontal attack on personal law, it will survive with a tenacity it has been unable to show in countries where the majority of the population are and always have been Muslims," said eminent jurist Duncan M. Derrit. This author is for uniform civil code in a piecemeal manner.

The article by RSS ideologue M.G. Vaidya ('The price of personal law', IE, November 1) has done a great disservice to the Uniform Civil Code (UCC) debate as he has explicitly said that Muslims and Adivasis should lose their right to vote in Parliament and state assembly elections if they refuse to accept the UCC. So the cat is finally out of the bag.

But then, hold your breath. Ravishankar Shukla, the premier of the central provinces and the first Congress chief minister of Madhya Pradesh, in a two-part article carried by Kalyan in July and August 1947 had argued that "Hindustan should become a Hindu rashtra and its state religion should be Hinduism. Hindus or non-Muslims should hold the top posts. Any person who does not believe in Hindu culture should not be made a part of the government of Hindustan." Shukla, a member of the Constituent Assembly, went on to say that Muslims should not be given citizenship rights. Thus, Vaidya alone should not be criticised.

Let us recall the history of the Hindu right's opposition to the Hindu Code Bill. The RSS, Hindu Mahasabha, Dharma Mahamandal, Akhil Bharatiya Dharma Sangh and several other organisations fiercely opposed the Hindu code Bill. The most vociferous critics of reforms in Hindu law in the 1940s and 1950s are now arguing for the UCC. The RSS itself was leading the opposition. As many as 79 public meetings were organised in 1949 by the RSS in Delhi to oppose the Hindu Code Bill which was termed as an atom bomb on Hindus.

It is true that Shyama Prasad Mukherjee said in Parliament that instead of the Hindu Code Bill, the government should bring in the UCC. There was much substance in this argument and Nehru indeed did a disservice to Muslim women by not bringing reforms for all communities in one go. Hindu law reform proposals received a lot of opposition not only from the extreme right but also from Congress leaders such as Vallabhbhai Patel, deputy prime minister, Pattabhi Sitaramayya, Congress president, Ananthasayanam Ayyangar, speaker of the constituent assembly. Madan Mohan Malviya and Kailash Nath Katju also opposed the reforms. When the debate on the Hindu Code Bill took place in 1949, as many as 23 out of 28 speakers who participated in the debate opposed it. On September 15, 1951, Rajendra Prasad threatened to use his powers of returning the bill to Parliament or vetoing it. Nehru had to concede and the bill could not be passed.

In 1949 itself, the Hindu right had formed an All-India Anti Hindu Code Bill Committee under the leadership of Swami Karpatri Maharaj who made even Ambedkar's "low" caste an issue. Karpatri justified unregulated polygamy and freely quoted Yajnavalkya:

"If the wife is a habitual drunkard, a confirmed invalid, a cunning, a barren or a spendthrift woman, if she is bitter-tongued, if she has got only daughters and no son, if she hates her husband, (then) the husband can marry a second wife even while the first is living." Geeta Press's Kalyan magazine published a number of articles which favoured polygamy, opposed the daughter's right to inheritance and questioned the Constituent Assembly's right to legislate on religious matters.

If we are interested in reforms, just like the Hindu Law Reforms Committee formed in 1941, the Modi government should constitute a Muslim Law Reforms Committee, a Tribal and Indigenous Law Reform Committee and Christian and Parsi Law Reforms Committees, and based on their recommendations, take the UCC process forward. We would then need a Hindu Law Committee as well, as some of the existing provisions such as solemnisation of marriage, kanyadaan, joint family, preference of issueless husband's parents in the self-acquired property of the daughter-in- law etc. may not find a place in the UCC and provisions like dower or nikahnama (prenuptial contract) are to be incorporated. Is the RSS of 2016 ready for these changes?

The writer is vice-chancellor NALSAR University of Law, Hyderabad. Views expressed are personal

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/uniform-civil-code-triple-talaq-muslim-personal-law-board-ucc-4368783/

✦✦✦

Sample of the Handbill for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State and District Units and distribute.

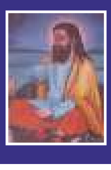
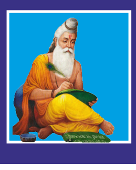
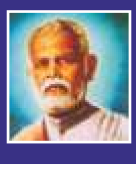
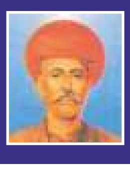
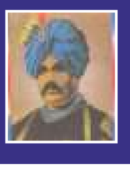
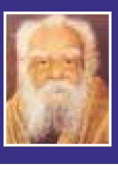
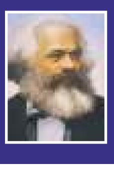

All India Confederation of SC/ST Organisations

19th Maha Rally

On

28 Nov 2016

at

Ramlila Ground, New Delhi

Dr. Udit Raj
National Chairman

Friends,

The problems faced by us, Dalits, tribals and backwards, are not just political, but due to social and economic reasons also. Whosoever may be in power, atrocities and discrimination will continue. Atrocities against us have occurred even where a Dalit was the Chief Minister. Dr. Ambedkar had said that without social democracy, political democracy will be meaningless, and for this, we must change society - through deeksha into Buddhism, abolition of superstitions, creation of a caste less society; at least, caste divisions amongst Dalits must be annihilated. Through all this, we can understand that thousands of years of inequalities and exploitation must be fought regularly, even if the Government is headed by Dalits or backwards. 5 anti-reservation orders were issued by DOPT when there was Social Justice Government at Centre. When Ku. Mayawati was the Chief Minister; we lost reservation in promotion case in Lucknow High Court. These examples make it amply clear the need to struggle on a regular basis. Our parents gave birth to us, but we got reservation only through the efforts of Dr. Ambedkar. Reservation was given not only for our own benefits, but to fight for other deprived brothers and sisters. This is why, irrespective of whether one be a Minister or a Member of Parliament or a sarpanch or an officer; they are all responsible to fight for the empowerment of society. In Jhajjar, Haryana 5 Dalits were killed for skinning the carcass of a dead cow; everyone knows the recent happenings in Una in Gujarat. Still, some people treat us as less than animals.

The All India Confederation of SC/ST Organisations was formed in 1997 to fight against 5 anti-reservation orders, and our fight began through rallies, agitations etc. The rally organised by the Confederation on 11th December 2000 at Ramlila Maidan, New Delhi was one of the largest in the history of independent India; this built pressure on the Govt., the 81st, 82nd and 85th Constitutional Amendments were passed and reservation was saved. On 4th November 2001, lacs of people took deeksha into Buddhism under the leadership of the Confederation. In 2006, we fought and won the Nagaraj case in the Supreme Court, related to the 85th Constitutional Amendment. We stood with OBC reservation in higher education in 2006. When the Anna Hazare movement pressed for a Lokpal Bill, we agitated against it and presented the Bahujan Lokpal Bill, and due to that, reservation was introduced here as well. Otherwise, the Lokpal could have become the largest platform for exploitation of SC/STs and OBCs by bringing fictitious cases of corruption.

In 2008, Ku. Mayawati, the then Chief Minister of Uttar Pradesh, passed orders that the Prevention of Atrocities Act, 1989, which included 22 atrocities, be applied only in cases of murder and rape. Then we fought against this in the Allahabad High Court by filing a Public Interest Litigation and it was restored to its original form. This Act was amended by Parliament in 2015, which included 123 atrocities. The Bill for reservation in promotion was to be passed by Parliament - it had been hoped that the Bill would be passed by now, but that has not happened. We have to start off a revolution to get this Act passed. From the time Dr. Udit Raj became a Member of Parliament, he has not left any opportunity to raise issues related to SC/STs in Parliament; it is likely that no other M.P. has raised as many issues – www.uditraj.com/gallery/video & www.youtube.com/user/druditraj

Dr. Udit Raj has introduced a private member Bill for reservation in the private sector in Parliament. Do the forward castes need reservation in private sector? Dr. Udit Raj has done his duty - why is society still sleeping? Why have lacs and crores of people not come out on the street and pressured political parties to pass a Constitutional Amendment for reservation in the private sector? More than half of reservation has already been diluted by outsourcing, contract system and ad hoc appointments. We have to continue fighting against this, but we cannot survive without reservation in private sector. To fight for our main demands of filling up of backlog vacancies, stopping outsourcing and contract system, regularization of safai karamcharis, caste certificates issued by one state being valid throughout the country, equal education etc., you must participate in the rally on 28th November 2016 at Ramlila Maidan, New Delhi at 11 AM to ensure that we get our rights.

By :

Brahm Prakash, Parmendra, Vinod Kumar, Ravindra Singh, N. D. Ram, Ramnandan Ram, (Delhi), Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath, Sushil Kumar, Neeraj Chak, Nirdesh Kumari (UP), Siddhartha Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Siddhartha Kamble, Suryakant Kiwande (Maharashtra), S. P. Jarawata, Dr. Mukhtiyar Singh, Mahasingh Bhurania (Haryana), Tarsem Singh, Dharshan Singh Chanded, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, Ranjeet Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, (U.K.), Alekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, Narender Kumar (M.P.), Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Naval Solanki (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamilnadu), K. Krishnan Kutty, Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathor, J. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, L. M. Oraon (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhar Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfor (Assam)

AIParisangh
9899766443
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

A silence that's deafening

The recent Maratha protest marches across Maharashtra, while a reflection of the farming crisis in the State, are essentially an expression of marginalisation of the community's lower and middle rungs

KUMAR KETKAR

If any political leader or pundit were to have said, even just four months ago, that lakhs and lakhs of Marathas were going to mobilise and march across Maharashtra, week after week, from Parbhani in Marathwada to the so-called "intellectual and knowledge capital" Pune, nobody would have believed that prognosis. Nobody, not even the powerful Maratha leadership, including the 'strongman' of Maharashtra, Sharad Pawar, had seen the turbulence beneath the superficial and deceptive calm in the community. Now it is obvious that the frustration and anger among the Marathas has been brewing intensely.

Most people outside Maharashtra do not understand the difference between the two phonetically similar sounding terms, Maratha and Marathi. Why, even the metropolitan Mumbaikar cannot comprehend the distinction. The broadcast media and panel pontiffs too are confused by the sudden tsunami-like Maratha marches, which they cannot simply ignore because of their sheer size and breadth. Indeed, the mobilisation is so grippingly picturesque that television cameramen and anchors cannot underplay it by pretending that Kashmir and the Cauvery water crisis are far more important!

The class divide among Marathas

The Maratha caste can be broadly compared with Jats in Rajasthan and Haryana or Patidar-Patels in Gujarat, primarily farmers. They are one-third of the State's population and Marathi is their mother tongue, though not exclusive to them. Within the community, there is a hierarchy observed very diligently, particularly when it comes to matrimony. However, irrespective of social hierarchy, they are all directly connected with agriculture, sons of soil, as it were. But there is another hierarchy, that of class. There are four class divisions.

The elite Marathas are directly related to power or power centres — ministers, chairmen of commissions, various boards, directors in cooperative banks, board members of sugar cooperatives, zilla parishad or gram panchayat chiefs, and so on. These Marathas are seen to not distinguish between the private and public.

The class just below them is the rich farmer, "bagayati" or cash crop farmer. They are powerful because they command respect on account of their wealth, which also gives them status and authority in the villages. They are not in political power directly, but they have political heft across parties as they finance candidates.

Next in the hierarchy comes the small or middle peasant, who survives on a season-to-season basis, is dependent on the vagaries of nature, is anxious about the monsoon, takes small loans to run the farm or for wedding expenses, and commits suicide if harassed by the bank or moneylender. The middle peasant aspires to be a rich farmer, and hence imitates the lifestyle of the well-off farmer. When he fails to live up to his projected image, distraught, he hangs himself.

The lowest and the last layer is that of the landless peasants and agricultural labourers who depend on government employment guarantee schemes and other benefits.

The only bond among this four-layered class structure is of caste. Being Maratha gives them a feeling of difference from the 'other' and an illusion of being important.

The power elite have everything going for them. The rich farmer's main worry is that he is not getting cheap labour because of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. His economic interest pits him against his Maratha brethren because of the class distinctions. The real frustration is among the small/middle farmers, the vast section of landless farmers and/or agricultural labourers. A young person among the lower classes of Marathas has had no opportunities for higher education, no possibilities of migrating to the cities for a better future, and certainly no avenues to new kinds of jobs — in the information technology sector, for instance. Unemployment, declining agriculture, compounded by severe drought and devastating floods, have threatened his very survival.

For the past two years these suffering classes waited with great expectation for "Achche Din". They had voted against the Congress because their condition saw no improvement during the years of Congress rule. They thought Narendra Modi would provide what the Congress-Nationalist Congress Party (NCP) alliance did not. Now, there's disillusionment.

Searching for an object of ire

Thus, multiple frustrations got accumulated and mixed up. But who should be held responsible? The Marathas are in power from sugar cooperatives to Mantralaya, the administrative headquarters of the State government. All parties, from the Congress, NCP, to the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena have large contingents of Marathas. In assemblies and local self-governments there is Maratha domination. And yet the lower- and middle-rung Marathas feel isolated, neglected, marginalised in the job market and denied opportunities in higher education.

The reservation policy gave Dalits an advantage vis-à-vis Marathas in getting admission in reputed colleges. Ironically, many of the State's private colleges and deemed universities are owned, run and managed by the Maratha power elite! Moreover, the subcaste, or parallel caste, Kunbi, was included in the Other Backward Classes (OBC) reservation category. That, too, has fuelled the demand for reservation among other larger Maratha groupings. The disgruntled Maratha youth, instead of wagging an accusing finger at the power elite of their own caste, began to see an enemy in the Dalit community, the 'beneficiaries' of the reservation policy.

The brutal rape and murder of a Maratha girl in July by a few Dalit youth in Kopardi village of Ahmednagar district provided these marginalised Maratha youth an opportunity to direct their wrath against the Backward Castes and OBCs. Though none of the recent Maratha marches have witnessed any diatribe against the Dalit community, the underlying message is that the mobilisation is targeted against the Dalits. Since the NCP founded and led by Mr. Pawar has the largest Maratha following, many commentators believe that he and his party are behind the movement. The Maratha elites are happy to face this charge, because they get credit for channelling the discontent when they are at best only supporting from behind the scenes what is essentially a spontaneous expression of mass (and class) frustration.

In the past it was the Brahmin (caste and class) that was the 'enemy' of the Marathas (self-declared Bahujan). The Dalits and OBCs too regarded Brahminism as the main 'enemy'. Demographically, this upper caste had just about 4 per cent presence in society but dominated education, bureaucracy, media and other institutions of power. That domination was sharply reduced following reservation, and a section of the Marathas too entered the corridors of power and influence. But still there were the vast armies of lower- and middle-end Maratha youths deprived of participation in the mainstream economic, political and cultural affairs. Around 200 Maratha families have kept the reins of power in their hands, claim organisers of the protest movement.

Rage of the have-nots

As stated in the beginning, the marches are a reflection of the massive crisis in the agricultural economy of Maharashtra. That is the reason the demand for the implementation of reports of the M.S. Swaminathan-led National Commission on Farmers between 2004 and 2006 has acquired importance in this agitation. The farmer is denied competitive prices for his produce, affordable prices for the input elements, relief and support during drought, famines and floods, and help from financial institutions when it is the need of the hour.

This hapless and helpless small and middle farmer is seeing around him the new wealth, new opportunities, new jobs, new lifestyles that he too aspires to. The urban haves and rural haves have cornered the new wealth, making him the new poor. The new poverty is not poverty imposed on him by nature or overall backwardness; it is enforced by the ruling class and the ruling government and the ruling establishment. He knows who the 'enemy' is: it is in his neighbourhood and his community. That is why all the marches are silent protest processions, perhaps. The marches are disciplined, clean, huge and silent, with massive participation from women of all age groups and girl students who are angry because they feel the future is being snatched away from them.

The silence of the lakhs of marchers is deafening and the elite — Maratha or Brahmin or Dalit — are feeling threatened. It is a silent political bomb ticking and could explode anytime, devastating all that we think is stable and settled.

Kumar Ketkar is a veteran journalist and Chief Editor of 'Dainik Divya Marathi'.

http://www.thehindu.com/opinion/lead/kumar-ketkar-writes-on-maratha-community-protests-a-silence-thats-deafening/article9163 837.ece

✦ ✦ ✦

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 24 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 November, 2016

Donations for Rally on 28 Nov & other instructions

Friends,

The recently launched demonetization drive by which notes of value Rs. 500 and Rs. 1000 are no longer legal tender is known to all of you. While this drive is of immense benefit to the nation, despite some small short term inconveniences, you are also aware that the All India Confederation of SC/ST Organizations is conducting the 19th Annual Rally at Ramlila Maidan, New Delhi on 28th November 2016. For the last 18 years, the Confederation has been entirely funded by donations from people such as you who wish to give back to society to achieve Dr. Ambedkar's vision, and this year is no exception. Many of you have already made small donations, in cash and kind, for the success of the rally. Now, when the danger to reservation and our place in society is at an all time high, our rally which is to create pressure on the Government for fulfillment of our genuine demands such as reservation in promotion, reservation in private sector, ending atrocities against Dalits, ending outsourcing and contract system, should not be hampered by this demonetization drive and subsequent lack of funds. So far practice to fund the rally was mainly in cash, now we have to abide by Government rules, so it is better to deposit donations in the Confederation bank account. Those who wish to make donations to the Confederation for the success of the rally and fulfillment of our genuine demands can make donations either in cash to Mr. Sumit in the Central office or in the bank account of the Confederation in old notes of Rs. 500 and Rs. 1000, as per the account details below. You can also transfer donations directly through internet banking or mobile banking in the bank account of the Confederation. There is no limit on fund transfer through internet or mobile banking. Please contact Mr. Sumit (9868978306) in the Central office for any queries in this regard.

Customer Name: ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANISATION
Account no: 30899921752
CIF No: 85626065749
Saving Bank Account State Bank of India Chandralok Building
IFSC Code: SBIN0001639

For information and promotional material regarding Confederation, confirmation of Railway tickets for rally and other information, contact Sumit (9868978306). For information about stay and food arrangements in Delhi for rally, contact Sanjay Raj (9654142705). Those attending the rally should immediately let us know about the number of people attending with them so arrangements for stay and food can be made for them. Railway employees can contact Sachin (9650035350) regarding issues related to the Association, queries etc.

Dr. Udit Raj
National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations

Sample of the Poster for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State and District Units and distribute.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya